भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5073
दिनांक 24.03.2026 को उत्तरार्थ

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

†5073. श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री विजय बघेलः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री गोपाल जी ठाकुरः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री अनन्त नायकः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
डॉ. भोला सिंहः
श्री भोजराज नागः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री मनोज तिवारीः
श्री शंकर लालवानीः
सुश्री कंगना रनौतः
श्रीमती संजना जाटवः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री जगदीश शट्टरः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री नलिन सोरेनः
श्री जुगल किशोरः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री रोडमल नागरः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री हरीभाई पटेलः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर शामिल किए गए ग्राम पंचायतों का प्रतिशत और कुल संख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र **, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश** और जलगांव जिले, देवास और शाजापुर जिले, पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, दुर्ग और बेमेतरा, झारखंड के दुमका जिले, छत्तीसगढ़, भरतपुर और पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी जिलों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पोर्टल के वास्तविक समय लेखांकन, योजना और कार्य-निगरानी मॉड्यूल पूरी तरह से चालू कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ग्राम पंचायतों द्वारा इन मॉड्यूलों के उपयोग का ब्यौरा क्या है और डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से योजनाबद्ध, अनुमोदित और मॉनीटर किए गए कार्यों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार कितनी है;

(घ) क्या निधियों और व्यय का शुरू से अंत तक पता लगाने के लिए सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और अन्य केन्द्रीय डाटाबेस के साथ पोर्टल का एकीकरण पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो पंचायत स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी, समय पर निधि के उपयोग और पंचायत स्तरीय सूचना तक जनता की पहुंच में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिला-बार क्या उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) दिनांक 19.03.2026 के अनुसार, कुल 2,58,730 ग्राम पंचायतों में से 2,52,742 (97.68%) ग्राम पंचायतों को ईग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश सहित राज्यवार आंकड़ा अनुलग्नक में दिया गया है। ग्राम पंचायतों के ऑनबोर्डिंग की स्थिति के संबंध में जिलावार आंकड़ा, ईग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे https://egramswaraj.gov.in/pfmsDashboardNew.do पर देखा जा सकता है। इन जिलों में जलगांव, देवास और शाजापुर (पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत) शामिल हैं।

(ख) एवं (ग) पंचायती राज मंत्रालय, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज में पारदर्शिता, कार्यदक्षता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना है। मंत्रालय ने योजना, लेखांकन, बजट और कार्य प्रगति की निगरानी जैसे पंचायती कार्यों को सरल बनाने के लिए ई-ग्रामस्वराज नामक एक लेखांकन ऐप शुरू किया है। ये मॉड्यूल मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और दुर्ग, बेमेतरा, दुमका जैसे जिलों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और भरतपुर और पाली जैसे संसदीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं। राज्य वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। जिलावार आंकड़ा ईग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे https://egramswaraj.gov.in/pfmsDashboardNew.do पर देखा जा सकता है।

(घ) जी हाँ। ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों और व्ययों की निर्बाध, एंड-टू-एंड ट्रैकिंग (शुरू से अंत तक)

सुनिश्चित करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण से निम्नलिखित कार्यों को सुगम बनाया गया है:

- पंचायत द्वारा धन का वास्तविक समय में हस्तांतरण
- व्यय का पारदर्शी लेखांकन और ट्रैकिंग
- बेहतर वित्तीय अनुशासन और लेखापरीक्षा

इसके अलावा, डेटा की एकरूपता बढ़ाने और शासन के परिणामों में सुधार करने के लिए पोर्टल को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भाषिनी जैसे अन्य प्रासंगिक प्रणालियों/डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है।

(ङ) ईग्रामस्वराज पोर्टल के एकीकरण और परिचालन के परिणामस्वरूप मापने योग्य सुधार हुए हैं, जिनमें निम्न सुधार शामिल हैं:

- वास्तविक समय लेखांकन और पंचायत लेनदेन की सार्वजनिक दृश्यता के माध्यम से बढ़ी हुई वित्तीय पारदर्शिता
- जियो-टैगिंग और प्रगति की ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से कार्यों की बेहतर निगरानी
- प्रत्यक्ष हस्तांतरण और प्रक्रियात्मक देरी में कमी के कारण समय पर धनराशि का उपयोग
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंचायत-स्तरीय जानकारी तक आमजन की पहुंच में वृद्धि

इन मापदंडों पर राज्य वार मापने योग्य संकेतकों को अनुलग्नक में दिया गया है। जिलावार आंकड़ा ईग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे https://egramswaraj.gov.in/pfmsDashboardNew.do पर देखा जा सकता है

*****

अनुलग्नक

"ई-ग्रामस्वराज पोर्टल" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5073 जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ई-ग्रामस्वराज को राज्यवार अपनाने की स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायत एवं समकक्ष	eGS-PFMS पर ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायत एवं समकक्ष	स्वीकृत भुगतान (₹ करोड़ में)	योजना वर्ष 2025-26 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा अपलोड की गई विकास योजनाओं की कुल संख्या	योजना वर्ष 2025-26 हेतु लिए गए गतिविधियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13327	13320	13032	1485	13320	891401
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	1509	52	2093	87923
3	असम	2663	2189	2112	481	2243	112656
4	बिहार	8054	8054	8048	2695	8053	580616
5	छत्तीसगढ़	11692	11687	11337	761	11648	644990
6	गोवा	191	191	117	19	191	9282
7	गुजरात	14619	14596	13878	1676	14563	558473
8	हरियाणा	6227	6227	6029	950	6221	246797
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3577	357	3607	234050
10	झारखंड	4345	4345	4275	401	4344	323797
11	कर्नाटक	5949	5949	5938	1871	5940	411311
12	केरल	941	941	938	462	941	74437
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22258	2129	22970	1141812
14	महाराष्ट्र	28002	27934	26541	3512	27904	1750255
15	मणिपुर	3175	161	113	2	161	21227
16	मेघालय	0	0	0	0	0	
17	मिजोरम	855	841	817	147	808	6691
18	नागालैंड	1312	984	0	0	0	
19	ओडिशा	6794	6794	6786	1814	6794	155219
20	पंजाब	13236	13233	12450	1591	13231	45644
21	राजस्थान	13128	11184	10798	2130	11173	209418
22	सिक्किम	199	199	197	25	199	3102
23	तमिलनाडु	12482	12482	12442	1537	12393	157188
24	तेलंगाना	12760	12679	11684	431	12131	117419
25	त्रिपुरा	1194	1194	1192	159	1193	38040
26	उत्तराखंड	7817	7792	7102	391	7766	60512
27	उत्तर प्रदेश	57695	57693	57668	12248	57678	451024
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3337	2114	3337	256602
कुल योग	—	**258730**	**252742**	**244175**	**39441**	**250902**	**8589886**